ई-केवाईसी नहीं कराया तो रुकेगी सब्सिडी

सब्सिडी पात्र उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए नियम सख्त कर दिए हैं

10 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले सब्सिडी के पात्र नहीं होंगे.

नई दिल्ली, 3 जुलाई. रसोई गैस (एलपीजी) उपभोक्ताओं के लिए जुलाई की शुरुआत के साथ सब्सिडी से जुड़े नियम और सख्त हो गए हैं. सरकार और तेल विपणन कंपनियों ने लाभार्थियों का सत्यापन तेज कर दिया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी केवल वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे.

इसी क्रम में इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है. जिन उपभोक्ताओं ने 30 जून तक ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनकी सब्सिडी अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है. सरकार के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक ग्राहक सत्यापन (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया आधार आधारित सत्यापन पर आधारित है. इससे फर्जी, डुप्लीकेट और अपात्र गैस कनेक्शनों की पहचान करना आसान होगा. जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा ई-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, जिन लोगों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द इसे पूरा करने की सलाह दी गई है. एलपीजी सब्सिडी के पात्रता नियम पहले की तरह लागू रहेंगे. यदि किसी परिवार की वार्षिक कर योग्य आय 10 लाख रुपये से अधिक है, तो वह सब्सिडी का लाभ नहीं ले सकेगा. इसके अलावा, जिन उपभोक्ताओं की जानकारी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती या जिनका सत्यापन लंबित है, उनकी सब्सिडी भी प्रभावित हो सकती है.

> सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य किसी पात्र उपभोक्ता को परेशानी में डालना नहीं, बल्कि सब्सिडी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है. पिछले कुछ वर्षों में फर्जी लाभार्थियों और डुप्लीकेट गैस कनेक्शनों को हटाने के लिए लगातार अभियान चलाए गए हैं. ई-केवाईसी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बीएलएस ने अतियाती टेक्नोलॉजीज खरीदी

नयी दिल्ली, 03 जुलाई तकनीक आधारित डिजिटल सेवाएं देने वाली कंपनी बीएलएस ई-सर्विसेज ने बेंगलुरु की एआई आधारित बैंकिंग टेक्नोलॉजी कंपनी अतियाती टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड की शत-प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है. इस अधिग्रहण के लिए कंपनी ने 157 करोड़ रुपये का नकद भुगतान किया है. अतियाती टेक्नोलॉजीज बैंकों और वित्तीय संस्थानों को एआई आधारित डिजिटल बैंकिंग समाधान, माइक्रो-लोन प्लेटफॉर्म और गांव-गांव तक बैंकिंग पहुंचाने वाली सेवाएं उपलब्ध कराती है. कंपनी 35 से अधिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ काम करती है. इसके पास 25,900 से अधिक कस्टमर सर्विस प्वाइंट हैं, जोदेश के लगभग एक लाख गांवों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाते हैं.

पीएफ के जानें कई बड़े फायदे

नई दिल्ली, 3 जुलाई. नौकरीपेशा लोगों की सैलरी से हर महीने कटने वाला प्रोविडेंट फंड केवल एक अनिवार्य बचत योजना नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित यह योजना कर्मचारियों को नौकरी के दौरान और रिटायरमेंट के बाद भी कई तरह के फायदे देती है. लेकिन अधिकतर लोग इसे सिर्फ रिटायरमेंट फंड मानकर नजरअंदाज कर देते हैं.

पीएफ का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान हर महीने जमा होता है. इस जमा राशि पर हर साल ब्याज भी मिलता है, जो समय के साथ कंपाउंडिंग के जरिए एक बड़ा फंड तैयार कर देता है. यही पैसा रिटायरमेंट के

समय आर्थिक सहारा बनता है.

इसके अलावा, पीएफ का एक हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है. तय शर्तें पूरी होने पर कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन मिल सकती है, जो नियमित आय का स्रोत बनती है.

पीएफ योजना में बीमा सुरक्षा का लाभ भी मिलता है. कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत यदि नौकरी के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक सहायता मिलती है, वह भी बिना किसी अलग प्रीमियम के. जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने पीएफ खाते से एडवांस राशि भी निकाल सकते हैं. यह सुविधा घर खरीदने, गंभीर बीमारी के इलाज, बच्चों की पढ़ाई, शादी और अन्य जरूरी परिस्थितियों में उपलब्ध होती है.

> आज के समय में ईपीएफओ की ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं. जैसे बैलेंस चेक करना, पासबुक डाउनलोड करना, केवाईसी अपडेट करना और नॉमिनी जोड़ना—ये सभी काम अब घर बैठे किए जा सकते हैं. पीएफ सिर्फ सैलरी से कटने वाली रकम नहीं है, बल्कि यह बचत, पेंशन, बीमा, टैक्स लाभ और आपातकालीन सहायता का पूरा पैकेज है. इसलिए हर कर्मचारी को समय-समय पर अपना पीएफ खाता जरूर जांचना चाहिए और इसे लंबे समय तक सुरक्षित निवेश के रूप में बनाए रखना चाहिए

अनपढ़ महिला अल्बीना एक्का बनी सफल बिजनेस वुमन

रांची (झारखंड), 3 जुलाई मेहनत और हौसले के आगे शिक्षा की कमी भी बाधा नहीं बन सकती—इस बात को झारखंड की राजधानी रांची के पास पलांडू गांव की रहने वाली अल्बीना एक्का ने सच कर दिखाया है.

पढ़ना-लिखना न जानने के बावजूद उन्होंने चीकू की खेती से एक सफल बिजनेस खड़ा किया है और आज वह एक प्रेरणादायक महिला उद्यमी बन चुकी हैं.

अल्बीना एक्का के पास करीब 2 एकड़ जमीन है, जिसे उन्होंने सरकार की योजना के तहत लीज पर लिया है. इसी जमीन पर उन्होंने लगभग 2000 चीकू के पौधे लगाए, जो अब बड़े पेड़ों में बदल चुके हैं. आज उनकी खेती से हर दिन करीब एक टन चीकू का उत्पादन होता है, जिसकी सप्लाई झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा और अन्य राज्यों में की जाती है. वे बताती हैं कि उनकी फसल की गुणवत्ता काफी अच्छी है क्योंकि वे पूरी तरह ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करती हैं. इस खेती में लगभग 25 लोग नियमित रूप से काम करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला है.

क्यूबीई बनी राहेजा क्यूबीई की एकमात्र मालिक

मुंबई, 3 जुलाई 2026 ऑस्ट्रेलिया की वैश्विक बीमा कंपनी इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड ने भारतीय बीमा कंपनी राहेजा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बची हुई हिस्सेदारी भी खरीद ली है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी का 100 प्रतिशत स्वामित्व क्यूबीई के पास है.

यह अधिग्रहण प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड के साथ 18 वर्षों की संयुक्त भागीदारी के बाद पूरा हुआ है. इस बदलाव के साथ राहेजा क्यूबीई का नाम बदलकर केवल क्यूबीई कर दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि यह कदम भारत में उसके दीर्घकालिक विस्तार और विकास की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कंपनी के अनुसार, पूर्ण स्वामित्व मिलने के बाद उसे नए बीमा उत्पाद विकसित करने, आधुनिक तकनीक अपनाने, वैश्विक स्तर की कार्यप्रणालियों को लागू करने और परिचालन में नवाचार करने के अधिक अवसर मिलेंगे. इसका उद्देश्य भारतीय ग्राहकों को बेहतर, सरल और ग्राहक-केंद्रित बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना है.

क्यूबीई एशिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रॉब कोसोवा ने कहा, 'भारत दुनिया के सबसे गतिशील बाजारों में से एक है. हमें विश्वास है कि क्यूबीई की वैश्विक विशेषज्ञता और क्षमताओं के साथ हम यहां विकास के अगले चरण को आगे बढ़ाने और इस विशाल बाजार की दीर्घकालिक संभावनाओं का लाभ उठाने की मजबूत स्थिति में हैं.'

> **क्यूबीई एशिया के बारे में**
> क्यूबीई एशिया, क्यूबीई इंश्योरेंस ग्रुप लिमिटेड के अंतरराष्ट्रीय कारोबार का हिस्सा है. कंपनी का मुख्यालय सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और यह ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटीज एक्सचेंज में सूचीबद्ध है. क्यूबीई दुनिया के कई देशों में सामान्य बीमा और पुनर्बीमा सेवाएं प्रदान करती है.

भारत से डोनाल्ड ट्रंप ने कमाए 81 करोड़ रुपए

नई दिल्ली, 3 जुलाई: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कमाई में भारत का भी बड़ा योगदान सामने आया है. अमेरिकी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स की वित्तीय खुलासा रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने वर्ष 2025 में भारत से करीब 8.5 मिलियन डॉलर (लगभग 81 करोड़ रुपये) की आय अर्जित की. यह कमाई किसी प्रत्यक्ष निवेश या निर्माण कार्य से नहीं, बल्कि उनके नाम और ब्रांड के इस्तेमाल के बदले मिलने वाली लाइसेंस फीस से हुई.

रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप की कुल अनुमानित संपत्ति लगभग 5.7 अरब डॉलर है. वर्ष 2025 के दौरान उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी, रियल एस्टेट, लाइसेंसिंग समझौतों और निवेश सहित विभिन्न स्रोतों से 2.2 अरब डॉलर से अधिक की कमाई की. इनमें भारत उनके अंतरराष्ट्रीय रियल एस्टेट लाइसेंसिंग कारोबार के प्रमुख बाजारों में शामिल रहा.

भारत में ट्रंप ऑर्गनाइजेशन का कारोबार अमेरिका से अलग मॉडल पर चलता है.

भारतीय शेयर बाजारों में तेजी जारी

262 अंक की बढ़त पर रहा सेंसेक्स

95.15 अंक से आगे रहा निफ्टी

मुंबई, 03 जुलाई दूसरे एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में शुक्रवार को तेजी रही और बीएसई का सेंसेक्स 262 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ.

सेंसेक्स की शुरुआत 650 अंक चढ़कर हुई थी, लेकिन वह उस स्तर पर अंत तक टिक नहीं सका. कारोबार की समाप्ति पर सूचकांक पिछले कारोबारी दिवस की तुलना में 261.79 अंक (0.34 प्रतिशत) ऊपर 77,763.91 अंक पर रहा. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 95.15 अंक यानी 0.39 प्रतिशत चढ़कर 24,270.85 अंक पर बंद हुआ. दोनों प्रमुख सूचकांक लगातार तीसरे दिन मजबूत हुए हैं.

वृहत बाजार में मिलाजुला रुख रहा. निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 0.13 फीसदी गिर गया जबकि स्मॉलकैप-100 सूचकांक 0.04 प्रतिशत ऊपर बंद हुआ. आईटी, फार्मा, रियल्टी और स्वास्थ्य सेक्टरों में अच्छी लिवाली देखी गयी. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, ऑटो और टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद समूहों की कंपनियों में बिकवाली का जोर रहा. सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलॉजीज का शेयर पौने छह फीसदी और बजाज फिनसर्व का दो प्रतिशत से अधिक चढ़ गया.

रेनो ने क्विड का नया संस्करण पेश किया

नयी दिल्ली, 03 जुलाई फ्रांसीसी वाहन निर्माता रेनो ग्रुप की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रेनो इंडिया ने शुक्रवार को नयी रेनो क्विड बाजार में उतारने की घोषणा की.

कंपनी ने बताया कि इस नये संस्करण में डिजाइन, वेरिएंट लाइन-अप और कीमतों में बदलाव किये गये हैं. इसका उद्देश्य पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कार का स्वामित्व पहले से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना है.इस अपडेट में क्विड पर रेनो की नयी ब्रांड पहचान पेश की गयी है.

अहमदाबाद में अत्याधुनिक कंट्रोल सेंटर शुरू

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने किया उद्घाटन

तकनीकी एकीकरण एवं दक्षता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

अहमदाबाद, 3 जुलाई. यात्रियों को सुरक्षित, समयबद्ध एवं विश्वसनीय रेल सेवाएं उपलब्ध कराने तथा रेल परिचालन को अत्याधुनिक तकनीक से सुदृढ़ बनाने की दिशा में पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है.

अहमदाबाद मंडल में नवनिर्मित स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर का आज मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया. यह अत्याधुनिक नियंत्रण केंद्र अब पूर्ण रूप से कार्यशील हो गया है और उत्तर गुजरात क्षेत्र में रेल संचालन के 'केंद्रीय तंत्र के रूप में कार्य करेगा. लगभग 24,500 वर्ग फुट क्षेत्र में विकसित यह आधुनिक परिसर रेल परिचालन से जुड़े विभिन्न विभागों की नियंत्रण गतिविधियों को एक ही छत के नीचे एकीकृत करता है. इसके माध्यम से परिचालन दक्षता, समयपालन तथा यात्री सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित होगा. उद्घाटन के अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद मंडल निरंतर आधुनिक तकनीकों को अपनाकर भारतीय रेल के डिजिटल परिवर्तन को गति दे रहा है. उन्होंने कहा कि यह इंटीग्रेटेड कंट्रोल सेंटर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है.

समाचार विशेष

विधानसभा में बैसाखी नहीं चाहते विजय

चेन्नई. एआईएडीएमके के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री एमआर विजयभास्कर ने करूर से एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया. वे विपक्षी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लिस्ट में शामिल होने वाले ताजा नेता हैं.

उम्मीद है कि वे इस हफ्ते विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो जाएंगे, जिससे एआईएडीएमके की संख्या घटकर 41 रह जाएगी. यह घटनाक्रम मारुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के डीएमके के नेतृत्व वाले सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से 9 साल के गठबंधन के बाद अलग होने के दो दिन बाद हुआ है. वाइको ने टीवीके को समर्थन दिया है, खासकर उपचुनावों में. हालांकि एमडीएमके के दो विधायकों ने हाल ही में उगते सूरज के चुनाव चिह्न पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है. ये दोनों घटनाएं मुख्यमंत्री विजय की उस रणनीति के अनुरूप हैं, जिसका मकसद 234 सदस्यों वाली विधानसभा में टीवीके की संख्या बल को बढ़ाना और गठबंधन सहयोगियों पर अपनी मौजूदा निर्भरता से आगे बढ़कर एक अधिक आरामदायक बहुमत के करीब पहुंचना है. एआईडीएमके के छह नेताओं के इस्तीफे और विजय के त्रिची ईस्ट से रिजाइन के बाद जो सीटें खाली हुई हैं, टीवीके उनका इस्तेमाल अपनी पार्टी के माध्यम से इन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए करेगा. इन रिक्तियों के कारण विधानसभा की मौजूदा संख्या घटकर 227 और बहुमत का आंकड़ा घटकर 114 हो गया है.

फिलहाल, टीवीके की अपनी संख्या 107 है, जो बहुमत के आंकड़े से महज सात कम है. यदि टीवीके उपचुनावों में खाली हुई सभी सात सीटों पर जीत हासिल कर लेती है, तो 234 सदस्यों वाली विधानसभा में उसकी संख्या बढ़कर 114 हो जाएगी, जो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ चार कम होगी.

> **तमिलनाडु विधानसभा का समीकरण**
> अप्रैल के विधानसभा चुनावों में टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन शुरुआत में वह 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी. पांच सीटों वाली कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुई और उसे दो मंत्री पद मिले. विदुथलाई चिरुथाइगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने दो-दो सीटों के साथ समर्थन दिया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया-मार्क्सिस्ट ने दो-दो सीटों के साथ बाहर से समर्थन दिया.

डीएमके से और दूर हो रही है कांग्रेस

नई दिल्ली. ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी दशकों पुरानी सहयोगी डीएमके से दूरी बढ़ाती जा रही है. पहले तो चुनाव समाप्त होते ही उसने डीएमके से संबंध समाप्त किया और टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया.

टीवीके प्रमुख विजय ने कांग्रेस को सरकार में शामिल किया और इस तरह तमिलनाडु में कांग्रेस का 60 साल का सत्ता का सूखा समाप्त हुआ. इसके बाद डीएमके ने कांग्रेस से संबंध विच्छेद करने का ऐलान करते हुए लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी और लोकसभा में अलग बैठने की जगह मांगी. हालांकि इसके बावजूद कई लोगों को उम्मीद थी कि अगले कुछ दिन में डीएमके और कांग्रेस फिर साथ होंगे. हाल के घटनाक्रम से ऐसा नहीं लग रहा है.

कांग्रेस ने एक तरह से डीएमके और उसके प्रमुख एमके स्टालिन को चिढ़ाते हुए अपने सांसद मणिक्कम टैगोर को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है. मणिक्कम टैगोर और स्टालिन का मामला वैसा ही है, जैसा बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी का है. विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे से पहले स्टालिन चाहते थे कि राहुल अपने नजदीकी मणिक्कम टैगोर को चुप कराएं और वार्ता से दूर रखें.

> असल में ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने भांप लिया है कि दक्षिण भारत में उसका समय आ रहा है. दक्षिण के पांच बड़े राज्यों में से तीन में उसका मुख्यमंत्री बन गया है. चौथा राज्य तमिलनाडु हो सकता है. क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि वहां द्रविड राजनीति समाप्त हो रही है और डीएमके व अन्ना डीएमके दोनों हाशिए में जाएंगे. नई ताकतें उभरेंगी. विजय के अलावा अन्नामलाई भी मजबूत होंगे. ऐसे में कांग्रेस भी अपनी जगह नए सिरे से बना सकती है.

नीतीश कुमार से मिले आरसीपी सिंह

पटना. बिहार की राजनीति में शनिवार को उस समय नई हलचल पैदा हो गई, जब जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे.

आरसीपी सिंह अपने समर्थकों के साथ नीतीश कुमार के 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचे. करीब 20 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई. इसके बाद आरसीपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की पुष्टि करते हुए लिखा कि उनकी नीतीश कुमार से आत्मीय बातचीत हुई. इसकी तस्वीर भी उन्होंने साझा की है. हालांकि, इस घटनाक्रम ने तब नया मोड़ ले लिया, जब आरसीपी सिंह के कुछ समर्थकों ने दावा किया कि उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी.

नई नियुक्तियां राहुल के हिसाब से

नई दिल्ली. कांग्रेस के सुप्रीम लीडर राहुल गांधी धीरे धीरे पार्टी पर पूरी पकड़ बनाने में लग गए हैं. कांग्रेस ने तीन राज्यों में प्रभारियों की नियुक्ति की है, जिनको देख कर लग रहा है कि उन पर राहुल की स्पष्ट छाप है.

कई तरफ से आलोचनाओं के बावजूद राहुल अपने लोगों को नियुक्त कर रहे हैं. ध्यान रहे पिछले दिनों कांग्रेस के बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बिहार में कृष्णा अल्लावरू को प्रभारी और राजेश राम को अध्यक्ष बनाए जाने की आलोचना की थी और कहा था कि इनकी वजह से कांग्रेस पार्टी का पिछले चुनाव में बुरा हाल हुआ. उन्होंने कहा कि अराजनीतिक लोगों को कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया जा रहा है, जिनको कोई अनुभव नहीं है. राहुल द्वारा की गई दूसरी नियुक्तियों पर भी सवाल उठे. लेकिन वे इन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. उन्होंने तीन नेताओं को तरक्की देकर तीन राज्यों का प्रभारी बनाया है. ये तीनों अपेक्षाकृत कम अनुभवी हैं. बीके हरिप्रसाद के कर्नाटक का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद हरियाणा में नए प्रभारी की नियुक्ति होनी थी तो राहुल ने महाराष्ट्र के संजय दत्त को प्रभारी बनाया. उत्तर प्रदेश में अविनाश पांडे जैसे बड़े नेता को हटा कर राजेंद्र पाल गौतम को बनाया और ओडिशा में अजय कुमार लल्लू को हटा कर लालजी देसाई को बनाया.

विशेष | **राजनीति से दूर नवजोत सिंह सिद्धू भी लड़ सकते हैं चुनाव**

चुनाव को लेकर कांग्रेस-बीजेपी ने बढ़ाई सक्रियता

चंडीगढ़. पंजाब में पिछली हार से सबक लेते हुए कांग्रेस चुनावों से पहले गुटबाजी खत्म करने में जुटी है. चर्चा है कि गुटबाजी से परेशान कांग्रेस हाईकमान पंजाब की पूरी लीडरशिप टीम को बदलने पर विचार कर रहा है. राहुल गांधी ने इसके लिए पंजाब के शीर्ष 5 नेताओं के साथ वन-टू-वन बैठकें की हैं.

कांग्रेस नेतृत्व की सक्रियता के बीच चर्चा सामने आई है कि पूर्व क्रिकेटर और सांसद रह चुके नवजोत सिंह सिद्धू से फिर सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं. चर्चा यह है कि वह निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे. पिछले दिनों उनकी पत्नी नजवोत कौर सिद्धू ने एक पार्टी बनाने के संकेत दिए थे, हालांकि इसके बाद कोई अपडेट सामने नहीं आया है.

ऐसे में जब कांग्रेस पंजाब में अपने

पारंपरिक कोर वोट बैंक को वापस पाने के लिए दलित-अल्पसंख्यक एकता पर फोकस कर रही है. पार्टी इन दोनों समुदायों को जोड़कर एक नया चुनावी समीकरण बनाने की कोशिश में है. तब राजनीतिक हलकों में यह अटकलें सामने आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू फिर कांग्रेस के जरिए ही सक्रिय हो सकते हैं. नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से सक्रिय राजनीति से दूर हैं, हालांकि वह जब अप्रैल 2023 में पटियाला जेल से जब रिहा हुए थे तब सिद्धू ने कहा था. जब भी इस देश में तानाशाही आई है, तब-तब एक क्रांति भी आई है और आज उस क्रांति का नाम राहुल गांधी है.

> **सिद्धू के बारे में क्या चर्चा?**
> पंजाब चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज होने के साथ चर्चा सामने आई है कि नवजोत सिंह सिद्धू सक्रिय राजनीति में लौट सकते हैं. उम्मी जताई जा रही है कि एक बार फिर वह कांग्रेस ज्वाइन करके ही राजनीति करें. अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो नवजोत सिंह सिद्धू के चुनाव लड़ने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है. नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में आने से पिहले लंबे वक्त पर बीजेपी में रहे थे.